जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 26 संख्याः 159 प्रभात अजमेर, शनिवार 8 जनवरी, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

सुप्रीम कोर्ट ने प्र.मंत्री सुरक्षा में चूक के मामले में सुनवायी शुरू की

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को प्र.मंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान चूक के प्रकरण से संबंधित कागजातों को एकत्रित कर अपने कब्जे में करने के निर्देश दिये

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चंडीगढ़ यूनियन टैरिटरी के डायरैक्टर जनरल व एन.आई.ए. के एक मनोनीत अफसर, प्रकरण से संबंधित कागजातों के संकलन में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मदद करेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को इस बात के लिये भी पाबंद किया है कि, इस प्रकरण की जांच के लिये उन दोनों द्वारा गठित पैनलों को आगे कार्यवाही करने से रोके, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण की सुनवायी नहीं कर लेता।
- फिलहाल केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति ने अपना कार्य शुरू कर दिया है तथा उस फ्लाई ओवर पर भी छानबीन की जहां प्र.मंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक खड़े रहने पर मजबूर हुआ था।
- पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया कि, उसने सुरक्षा में चूक प्रकरण पर एफ.आई.आर. दर्ज की है तथा दो सदस्यीय टीम गठित की है, चूक प्रकरण की जांच हेतु।
- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, राज्य सरकार ने प्र.मंत्री की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों की पर्याप्त तैनाती नहीं की और यह अपनी जिम्मेवारी निभाने में गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जो बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कह दिया है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा-चूक से संबंधित सभी रिकॉर्ड तत्काल सुरक्षित एवं संरक्षित स्थिति में रख लिये जाए, वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार एवं कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के बीच निरन्तर वाद-विवाद जारी हैं तथा प्रत्येक पक्ष कथित चूक के लिये दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा हैं।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बैंच ने पंजाब सरकार, पंजाब के पुलिस अधिकारियों, एस.पी.जी. तथा केन्द्र और राज्य की अन्य एजेंसियों को निर्देश दिये है कि वे इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल को आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध करायें।

बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं हिमा कोहली भी शामिल हैं, ने कहा कि रिकॉर्ड एकत्रित करने के कार्य में केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के महानिदेशक तथा एक एन.आई.ए. ऑफिसर, रजिस्ट्रार जनरल (आर.जी.) की मदद करेंगे। बैंच ने आर.जी. से कहा कि वे सारे रिकॉर्ड को फिलहाल अपनी सुरक्षित कस्टडी में रखे। बैंच ने कहा, ''केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के महानिदेशक तथा रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निर्दिष्ट एक एन.आई.ए. रिकॉर्ड एकत्रित करने में आर.जी. का सहयोग एवं सहायता करेंगे।''

सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र एवं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई सिक्युरिटी जेल

अजमेर, 7 जनवरी (कासं)। केंद्रीय कारागृह में कैदियों के पास मोबाइल मिलने के बाद अब राजस्थान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल में भी मोबाइल मिलने का खेल शुरू हो गया है। शुक्रवार को एक बार फिर हाई सिक्योरिटी जेल में एक मोबाइल फोन व चार्जर मिलने का मामला सामने आया है। पूरे मामले पर हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच कर रहे हैड कांस्टेबल अर्जुन राम ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से मिली शिकायत के अनुसार वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 में नहाने के खुले स्थान के पास कोने में फर्श की टाइल के नीचे एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। जेल प्रशासन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर थाना पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व अजमेर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कुछ वर्ष पूर्व अजमेर की जेलों में 55 से अधिक मोबाइल फोन बरामद हुए थे। अब राजस्थान में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हाई सिक्युरिटी में जेल में भी यह सिलसिला शुरू हो गया है?

'पंजाब में राष्ट्रपति शासन?'

पंजाब के मु.मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने कहा कि, प्र.मंत्री की जान को खतरे का भारी हंगामा कर भाजपा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है चुनाव से पहले

- चन्नी ने यह भी कहा कि, प्र.मंत्री की जान को खतरे की वजह पर भारी हंगामा करके, भाजपा ने पंजाब व पंजाबियों का मखौल उड़ाया है। हमने कई युद्ध लड़े हैं देश के लिये, मैंने यह भी कहा कि प्र.मंत्री के लिये सबसे पहले छाती पर गोली खाऊंगा। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ।

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के जीवन को खतरे को लेकर भाजपा का अत्यधिक दुष्प्रचार केन्द्र सरकार की इस ''गहरी साजिश'' का हिस्सा है कि विधानसभा चुनावों से पहले, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाये।

जहाँ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष सहित, विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के कथन की खिल्ली उड़ाई है कि वे उनके जीवन पर आये खतरे से बच गये, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने न्याय संगत क्रोध के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है। चन्नी ने कहा है, ''उन्होंने पंजाब और पंजाबियों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया तथा हमें हत्यारों के रूप में चित्रित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आश्चर्यजनक है पर सच है, ग्रोथ रेट 9.2 प्रतिशत रहेगी

ओमक्रॉन के कारण इकॉनमी ग्रोथ में अधिकतम एक प्रतिशत की ही कमी होगी

- मुख्य रूप से भारत में इस इकॉनमी ग्रोथ का कारण है कृषि व औद्योगिक उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि होना।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। वर्तमान वित्त वर्ष (अप्रैल 2021- मार्च 2022) के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित 9.2 प्रतिशत वृद्धि को लेकर उत्सव मनाना एक जल्दबाजी हो सकता है, इसका कारण यह कि कारोबार और अर्थव्यवस्था पर ओमक्रॉन का असर छोड़ना अभी शेष है। इसका वास्तविक प्रभाव अंतिम आंकड़ों में परिलक्षित होगा, जिन्हें मार्च 2022 में जारी किया जाएगा।

फिर भी, सरकार के अधिकारी ऐसा नहीं मानते कि ओमक्रॉन आर्थिक विकास पर कोई गहरा असर छोड़ेगा।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव ने गुरुवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि दर 1 प्रतिशत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी क्योंकि करोनावायरस की एक नई लहर का मुकाबला करने के लिए भारत पहले से अधिक बेहतर तरीके से तैयार है।

सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी अधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से कृषि और निर्माण क्षेत्रों के प्रदर्शन में हुए सुधार के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में पिछले वित्त वर्ष में हुए 7.3 प्रतिशत संकुचन की तुलना में 9.2 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 की राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमा के अनुसार एक वर्ष पूर्व में 7.2 प्रतिशत संकुचन की तुलना में निर्माण क्षेत्र में 12.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का अनुमान है कि खनन व उत्खनन में 14.3 प्रतिशत और व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार व ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित सेवाओं में 11.9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि होगी।

कृषि क्षेत्र में इस बार 3.9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान हैं जो कि पिछले वित्त वर्ष में दर्ज आर्थिक वृद्धि से 3.6 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुमाति 197.46 लाख करोड़ की अस्थायी अनुमानित जीडीपी की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 में अनुमानित जीडीपी 232.15 लाख करोड़ है।

भारत ने पिछले चार दशकों वित्तीय वर्ष 2020-21 में खराब आर्थिक प्रदर्शन का 7.3 प्रतिशत की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि दर्शायी थी। तब वह उन देशों में शुमार हो गया था जो कोविड-19 वैश्विक महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे।

अब अजय माकन भी हुए करोना संक्रमित

जयपुर, 7 जनवरी (कासं)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करोना पॉज़िटिव आने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन भी करोना पॉज़िटिव हो गए हैं।

माकन ने करोना की रिपोर्ट पॉज़िटिव आने के बाद खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने सभी से कहा है कि जो भी उनसे मिलें हैं, वे अपनी जांच करवा लें और करोना प्रोटोकॉल का पालन करें। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करोना संक्रमित होने के बाद अब सभी बैठकें वर्चुअल शुरू कर दी हैं।

- माकन ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है।

डब्ल्यु.एच.ओ. के 194 सदस्यों में से 92 वैक्सिनेशन के लक्ष्य से दूर रहे

लक्ष्य था कि, 2021 के सितम्बर माह तक सभी देश 10 प्रतिशत जनसंख्या का वैक्सिनेशन तथा दिसम्बर 2021 तक 40 प्रतिशत जनसंख्या वैक्सिनेशन करा लेंगे

- वैक्सीन सभी देशों को उपलब्ध नहीं है तथा कुछ देश अपनी जनसंख्या को एक के बाद एक बूस्टर इंजैक्शन लगवा रहे हैं, जबकि बाकी अरबों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है।
- यह वर्तमान माहौल करोना वायरस के नये-नये ''वेरिएन्ट'' पैदा करने के लिये बहुत माफिक है।
- डब्ल्यु.एच.ओ. के अनुसार ओमक्रॉन एक सुनामी है, जो चुपचाप पर लगातार फैल रहा है, इसे ''माइल्ड'' मानना भारी गलती है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। यह सच अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.एच.ओ.) जैसी वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों को परेशान कर रहा है कि ''कोविड-19 के डेल्टा वेरिएन्ट की तुलना में इसका हल्का संस्करण बताया जा रहा ओमक्रॉन एक सुनामी साबित होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा रहा है, उनकी जान ले रहा है और सशक्त माने जाने वाले स्वास्थ्य प्रशासन एवं सिस्टम के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ''तथापि डेल्टा वेरिएन्ट की तुलना में ओमक्रॉन कम गंभीर प्रतीत होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि इसे एक ''नरम'' लक्षणों वाले वेरिएन्ट की संज्ञा दी जाए।

डब्ल्यू.एच.ओ. प्रमुख टेड्रोस अदानॉम गैब्रियेसस कहते हैं कि ''कोई गलती ना करें। अस्पतालों में क्षमता से अधिक मरीज भर्ती हो रहे हैं और उनकी तुलना में मैडिकल स्टाफ भी कम है, जिसके कारण ना केवल कोविड-19 बल्कि अन्य रोगों के बीमारों व ऐसे घायलों की भी मौत हो रही है, जिन्हें समय पर उपचार देकर बचाया जा सकता था। शायद पहली पीढ़ी की वैक्सीन्स इसके सभी संक्रमणों व हस्तांतरणों को ना रोक पाए, लेकिन वे इस वायरस से होने वाली मौतों और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों के आंकड़े को कम करने में काफी कारगर बनी हुई हैं।''

टेड्रोस के अनुसार वैक्सीन लगने की वर्तमान दर के हिसाब से 109 देश ऐसे हैं जो जुलाई 2022 की शुरूआत तक अपने देश की 70 प्रतिशत आबादी का भी पूर्ण टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कुछ ही देशों में एक के बाद एक बूस्टर डोज़ लगाने से किसी वैश्विक महामारी का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि अरबों लोग अब भी पूर्णतया असुरक्षित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन निर्माता और इनके डोज़ डोनेट करने वाले देश नियत समय से पहले ही इनकी आपूर्ति कर दें ताकि प्राप्तकर्ता देशों को इन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)